

All India Muslim Personal Law Board's Reaction on Recitation of Saraswati Vandana and Vande Mataram in Schools

2251. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that U.P. Government had issued any order for compulsory recitation of "Saraswati Vandana" and "Vande Mataram" in Government schools in Uttar Pradesh; if so, the details thereof;

(b) whether the All India Muslim Personal Law Board has asked muslims to withdraw their children from Government schools where recitation of Vande Mataram and Saraswati Vandana has been made compulsory by the U.P. Government; and

(c) whether Central Government have taken any action against the U.P. Government for issuing such order which violates Article 28 of the Constitution of India; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) The Department of Education of the Government of Uttar Pradesh has issued a Govt. order dated 17.4.97 under which time table for the Primary and upper Primary schools were prescribed for inculcating moral education for character building among the boys and girls studying in these Schools. The time table inter-alia included "Ish Vandana" at the beginning of the school followed by activities like physical exercise, yoga etc. and finally recitation of National Anthem before dispersal to class rooms.

Will a view to bring in further qualitative improvement in the elementary education in the State, the Department of Education, Government of Uttar Pradesh, issued certain instructions on 25.7.98 for introduction of "Kalpa Yojana" which inter-alia included recitation of "Vande Mataram and Vandana in front of the portrait of

Goddess Saraswati". The State Government has subsequently withdrawn the orders issued in this regard.

(b) No such information has been received in this Ministry from All India Muslim Personal Law Board.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में नियुक्त किये गये नये शिक्षक

2252. श्री डी.बी. यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में कुल कितने नये शिक्षकों की नियुक्ति की गई; और

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्थानान्तरण से संबंधित आवेदनों पर अपनाई जा रही नीति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी): (क) केन्द्रीय विद्यालयों में 2406 शिक्षक और नवोदय विद्यालयों में 1170 शिक्षक 1997-98 के दौरान नियुक्त किये गये थे।

(ख) शासी बोर्ड द्वारा 21.07.1998 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित स्थानान्तरण दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन में स्थानान्तरण किये जाते हैं जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

शासी बोर्ड द्वारा 21.7.98 को आयोजित उसकी 63वीं बैठक में यथा अनुमोदित स्थानान्तरण संबंधी दिशा-निर्देश

1. सामान्य नीति यह होगी कि शिक्षकों को जिसमें उप-प्रधानाचार्य भी शामिल हैं, बार-बार स्थानान्तरित न किया जाए। केवल संगठनात्मक कारणों से अथवा अनुरोध पर या चिकित्सा पर अथवा इन दिशा-निर्देशों में की गई व्यवस्था के अनुसार ही सामान्य स्थानान्तरण किये जाएंगे।

2. साधारणतः ऐसी कोई निर्धारित समयावधि नहीं होगी जिसके बाद किसी शिक्षक/उप-प्रधानाचार्य को स्थानान्तरित करना आवश्यक हो। परन्तु साधारणतः किसी केन्द्र पर रहने की अधिकतम अवधि प्रधानाचार्यों/शिक्षा अधिकारियों के मामलों में 5 वर्ष